सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• RNI NO.:PUNHIN/2019/77863 • www.jalandharbreeze.com

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 4 DECEMBER TO 10 DECEMBER 2019 • VOLUME-16 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

सफलता की कुंजी

भूल होना प्रकृत्ति है,
मान लेना संस्कृति है,
और उसे
सुधार लेना प्रगति है!

अनमोल विचार

कामयाब होने के लिए
अच्छे मित्रों की
जरूरत होती है
और ज्यादा कामयाब होने
के लिए अच्छे शत्रुओं की
आवश्यकता होती है!
-चाणक्य

भ्रष्टाचार तेरी जय जयकार लोगों में मची पड़ी है हाहाकार

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

अंग्रेजी का एक मुहावरा है Honesty is the Best Policy गलत और बिल्कुल गलत यह आजादी से पहले का मुहावरा है जो आज नहीं चलता आजकल प्रशासन में ईमानदारी का मतलब है बेवकूफी। ईमानदार रहोंगे तो परेशान रहोगे। क्योंकि भ्रष्टाचारियों की और प्रभावशालीयों की प्रशासन तक पूरी पैठ होती है, वोट की राजनीति तुम्हें ईमानदारी से काम करने ही नहीं देगी चाहे आप जनहित में कार्य करो या राष्ट्रहित में तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की सजा मिलेगी तुम्हारी सीट बदल दी जायेगी। हो सकता है विभाग और शहर भी बदल दिया जाये पिछले दिनों लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी के साथ लगते रोड़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण (नाजायज धक्केशाही से किये गये कब्जे) जो दुकानदारों द्वारा सरकारी जमीन रोड बर्म पर किये गये थे एक ईमानदार अधिकारी द्वारा हटा दिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप आम विद्यार्थियों नागरिकों को और यातायात को सुविधा जनक रास्ता भी मिला था और संदिगध गतिविधियों में लिप्त लोग भी गायब हो गये थे कुछ जगह तो आजकल रोक लगाकर यूनिर्वसिटी ने रोक रखी है कुछ आटो रिक्शा वालों ने और कुछ बस कन्डकटर की धक्केशाही द्वारा सड़क रोक रखी है सामान्य लोगों बालको और वृद्धों का सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, सामने बने पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, पैट्रोलिंग पुलिस, पुड़ा-प्रशासन सभी भागीदार है।

जिला प्रशासन की तो बात ही क्या आज तक कभी स्वास्थय विभाग, स्वच्छता एवं सैनेट्री-विभाग के किसी अधिकारी के दर्शन नहीं होते लगता है आफिस में ही चैकिंग हो जाती है रोड किनारे बनी वाटर ड्रेनेज की सफाई निर्माता ठेकेदार द्वारा एक बार भी नहीं करवाई गई होगी हां साथ वाली दिवारों के सौंदर्यकरण पर कमिश्न अच्छा मिला होगा अधिकारियों को अगर पूरा दिन तो क्या एक घण्टा बारिश हो जाये तो पूरा रोड पानी से भर जाता है और सड़क पर चलने की जगह ही नहीं रह जाती तब याद आती है उस ईमानदार अधिकारी की जिसने जन हित में इस नाजायज कब्जों को हटाकर अपनी ईमानदारी का प्रमाण दिया परन्तु लगता है उसे वही इनाम मिला होगा जो ईमानदार लोगों को प्राय मिला करता है ट्रांसफर क्योंकि वह दोबारा कभी नज़र नहीं आया।

क्या डी.ए.वी. प्रबंधन सो रहा ?

■ जालंधर/नीरज

बल्टन पार्क के नजदीक डी.ए.वी इंजीनियरिंग कालेज द्वारा जो विज्ञापन के बोर्ड लगाये गये है। इन विज्ञापन बोर्ड की सुविधा नगर-निगम जालंधर द्वारा शिक्षा संस्थानों को नि:शुल्क प्रदान करते समय यह नियम भी लागू किये जाते है कि प्रचार प्रसार हेतु लगाये जाने वाले बोर्ड के आसपास सौंर्दयकरण एवं स्वच्छता रखी जायेगी। इससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचेगी। जहां इस नि:शुल्क सुविधा का लाभ संबंधित विभाग अथवा संस्थान एवं आम जनता को भी होगा। डी.ए.वी. जैसी सस्थायें जो स्वयं वातावरण की शुद्धि हेतु प्रयास करती रहती है और इसका प्रचार भी करती है परन्तु खेद है कि ऐसी संस्था द्वारा जहां बोर्ड लगाये गये है वहां पर कूड़े के ढेर व बढ़ी हुई घास वातावरण को प्रदूषित करती है। क्या डी.ए.वी. प्रबंधन सो रहा है ? क्या डी.ए.वी. संस्थान को सिर्फ अपने विज्ञापनों से ही मतलब है ? नगर-निगम सख्ती से डी.ए.वी इंजीनियरिंग कालेज से नियमों की पालना करवाए जिससे वातावरण का सौंदर्यकरण हो सके।

यदि पानी हुआ बर्बाद-तो हम कैसे होंगे आबाद

नगर-निगम पानी की बर्बादी की रोकथाम में है नाकाम

■ जालंधर से प्रभात सूरी की विशेष रिपोर्ट

ऐसे ही कई स्लोगन (बिन पानी सब सूना) आपको कार्पोरेशन कार्यालय हो स्कूल अथवा अस्पताल कई सार्वजनिक स्थानों पर लिखे नजर आ जायेंगे आम जनता को जागरूक करने हेतु परन्तु इन स्लोगनस को छपवाने वाला नगर-निगम कार्यालय स्वयं सजग है। इस नारे को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर होगा नहीं न्यूज पेपर्स में अथवा नगर-निगम में ऐसे फोन नम्बर भी प्राय: देखने में आते है पानी की बर्बादी हेतु इस दिये नम्बर पर शिकायत करें बहुत कम लोग है जो करते होंगे शिकायत या यह आम लोगों का ही कार्य है। नगर निगम के जल-विभाग में नियुक्त कर्मचारी पूरे जालंधर शहर में भ्रमण करने वाले बिल्डिंग विभाग के कर्मचारी स्वच्छता सहायक एवं सम्बन्धित क्षेत्र के सीवेरज एंव स्ट्रीट लाईटस कर्मचारी एवं क्षेत्रीय कौंसलर एवं पार्टी कार्यकर्त्ता तथा प्रत्येक नगर-निगम में कार्यरत कर्मचारी एवं उनके सम्बन्धित परिवारिक सदस्य उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होने चाहिये जिन की जीविका उस विभाग द्वारा चल रही है हां उन्हीं लोगों का कर्त्तव्य है कि वे उस ओर ध्यान दें और निगम प्रशासन इस पर यथोचित कार्यवाही करे। प्राय सार्वजनिक प्रयोग हेतु लगाई गई टूटीयों, शौच प्रसाधनों चाहे वह अस्पतालों, स्कूलों एवं प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में लगे हो प्राय निरर्थक बहते पानी देखने में आते है, आम नागरिकों की छतों पर लगी पानी की टंकियां हो या उनके घरों की शोभा बढ़ाते लान या नागरिकों द्वारा उनके खाली प्लाटों पर की जाने वाली खेती बाड़ी अथवा भवन निर्माण सभी जगह हो रही है पेय जल बर्बादी।

क्या इसे रोकने के लिये सख्त कदम उठाये जा रहे है? 5 मरला प्लाटों में अथवा उससे कम एरिया के प्लाटो में जहां पानी की निशुल्क व्यवस्था पंजाब सरकार द्वारा की गई है एक निश्चित मात्रा में पानी प्रयोग हो उसके लिये मीटर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। कारें, बाईकस या अन्य वाहनों की धुलाई हेतु एक बाल्टी भर पानी पर्याप्त नहीं, गेट ओर गलियों की धुलाई हेतु पानी की बर्बादी करने वाले लोगों पर दण्डनीय कार्यवाही एवं जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए। जल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ईमानदारी से इस ओर ध्यान दे रहे है उत्तर है नहीं परन्तु आये दिन हम आय वृद्वि एवं अन्य भत्तों एंव सुविधायें देने हेतु धरना प्रदर्शन सक्रिय रूप से करने के लिए तत्पर है तब हमें अधिकार याद आते है परन्तु कर्त्तव्य हम भूल जाते है। कर्त्तव्य पूरा करने वाले ही अधिकार की बात करें तो अच्छा लगता है चाहे वे आम लोग हो अथवा कर्मचारी सबका कर्त्तव्य है पानी की बर्बादी को रोका जाये यही राष्ट्र हित में और मानवता के हित में भी होगा।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL
SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR
WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin

उक्ति

सही समय पर सही दिशा में प्रयास करना वरदान बन जाता है, जबकि सही समय पर गलत दिशा में प्रयास करना शाप और गलत समय पर गलत दिशा में प्रयास करना अभिशाप।

■ स्वामी विवेकानंद

www.jalandharbreeze.com

साप्ताहिक
4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2019
जालंधर ब्रीज

दखल

व्यवस्था को चुनौती देते नक्सली

झारखंड के गुमला में मतदान के दौरान नक्सली हमला यह बताने के लिए काफी है कि देश की आतंरिक सुरक्षा पर दहशत लगातार सिर उठा रही है। इस समय देश के 60 फीसद राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इन राज्यों में कहीं नक्सली हमलों की तीव्रता ज्यादा है तो कहीं पर कम। नक्सलियों के लिए पिछड़े इलाके मुफीद माने जाते हैं, इसलिए सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में विकास और आदिवासियों के बीच विश्वास बहाली के उपाय करने की जरूरत है।

झारखंड के गुमला में मतदान के दौरान नक्सली हमला यह बताने के लिए काफी है कि देश की आतंरिक सुरक्षा लगातार सिर उठा रही है। इससे पहले लातेहार में बीती शुक्रवार रात नक्सली हमला हुआ। इस हमले में पुलिस के चार जवान शहीद हो गए। यह हमला तब किया गया, जब चंदवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिसकर्मी आधिकारिक वाहन से जा रहे थे। इस हमले के लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मारे गए पुलिसकर्मियों में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है। इसी साल जून माह में झारखंड के सरायकेला-खरसावां में भी नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। हमले में पांच पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस तरह के हमले बार-बार सवाल खड़ा कर रहे हैं। नक्सली हिंसा से कई दशक तक जूझने के बाद भी सरकारें नक्सल नीति की दिशा तय करने की चुनौतियों से जूझ रही हैं। यह अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रयासों में है या फिर कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है। नक्सलवाद के अंतर्गत आने वाले लाल गलियारे की हिंसा पिछले पांच दशकों से जारी है।

देश के 21 राज्यों के लगभग 250 जिलों को प्रभावित करने वाला नक्सलियों का यह इलाका आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन इलाकों में अपहरण, फिरौती, डकैती, बम विस्फोट, निर्ममता से हत्याएं, अवैध वसूली, विकास को बाधित करने की कोशिशें तथा लोकतांत्रिक सत्ता को उखाड़ फेंकने की इच्छा और समांतर सरकार चलाने की हिमाकतें होती रही हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने नक्सलियों को राज्य और केंद्र सरकारें अक्सर चुका हुआ घोषित करने की गलती करते रही हैं और हमेशा इसका जवाब बेहद कायराना मिलता रहा है। 25 मई 2013 को जीरम घाटी में हुए नक्सली हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन रैली पर आत्मघाती हमला कर दिया था, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं सहित 30 से ज्यादा कांग्रेसी मारे गए थे। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं को निशाना बनाने का यह सबसे वहशियाना कृत्य था।

नक्सलियों ने नेताओं को जिस बेरहमी से मारा उससे लोकतंत्र के प्रति उनकी नफरत का पता चलता है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सबसे बड़ा नक्सली हमला छह अप्रैल 2010 को हुआ था, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने जवानों को चारों ओर से घेर कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। साल 2009 में कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर लालगढ़ जिले पर नक्सलियों के कब्जे का घटनाक्रम भी बड़ा हैरान कर देने वाला था। माओवादियों ने इस इलाके को कब्जे में लेकर स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिसके बाद कई महीनों तक संघर्ष चला और आखिरकार सुरक्षा बल इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे थे। दरअसल, सामाजिक न्याय की स्थापना के नाम पर अस्तित्व में आई नक्सल विचारधारा अब हिंसा, रक्तपात और वैधानिक सत्ता के खिलाफ काम करने वाला ऐसा संगठन बन गया है जिसमें खूनी विद्रोह को स्वीकार कर लिया गया है।

भारत, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नक्सलबाड़ी में भूस्वामियों के खिलाफ संथालों ने तीर कमान लेकर जिस असमानता के खिलाफ हिंसक रुख अपनाया था, उसका बड़ा और हिंसक रूप देश के कई भागों में लगातार देखने को मिलता है। सन 1967 में ही ऑल इंडिया कमेटी ऑन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी का गठन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओड़िशा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और जम्मू-कश्मीर के नेता शामिल हुए थे और उन्होंने संगठन को मजबूत करने, सशस्त्र संघर्ष चलाने और गैर संसदीय मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इससे साफ था कि वंचितों, गरीबों और शोषितों के हितों के नाम पर स्थापित संगठन ने लोकतंत्र की वैधानिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए हिंसक और अलोकतांत्रिक रास्ता चुना।

आजादी के बाद जब देश बड़े बदलावों के लिए तैयार हो रहा था और सरकारें भूदान, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों से देश का पुनर्निर्माण करने को संकल्पबद्ध थीं, तभी नक्सलवाद का उदय होना शुरू हो चुका था जो हिंसक विचारधारा को पोषित करने वाला था। वर्ष 1969 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर नामक हिंसक समूह की स्थापना से यह साफ हो गया था कि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसका प्रभाव दक्षिण में भी हुआ और वहां पर भू स्वामियों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन के लिए 1980 में पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्लूजी) की स्थापना की गई। इस समय नक्सलवाद का प्रभाव स्थानीय रूप से बढ़ रहा था और उसमें मजदूर और गरीब लोगों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे थे। यह भारत के लिए राजनीतिक तौर पर अस्थिरता और क्षेत्रीय दलों के उभार का भी समय था।

इस समय माकपा भी अस्तित्व में आ चुकी थी जो लोकतंत्र में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती थी। 1977 के बाद भाकपा ने माकपा और दूसरी छोटी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिल कर वाम मोर्चे का गठन किया। व्यावहारिक तौर पर केरल सहित अधिकांश जगहों पर यह पार्टी माकपा के एक छोटे सहयोगी दल में बदल गई। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में वाम दल सत्ता में आए भी। नक्सलवाद की हिंसक विचारधारा को भी राजनीतिक कारणों से स्थानीय समर्थन मिलने से यह समस्या बढ़ती गई। नक्सलियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों को निशाना बना कर 90 के दशक में इसे देश की बड़ी आंतरिक चुनौती बना दिया। नक्सलियों ने बुनियादी रूप से पिछड़े हुए सुदूरवर्ती और भौगोलिक रूप से कटे इलाकों पर अपना प्रभाव कायम किया।

सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इससे निपटने के लिए 'ग्रे हाउंड्स' और 'कोबरा' जैसे बल तैयार किए। नक्सलियों के सफाए के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। यूपीए शासनकाल में नक्सलियों पर त्वरित कार्रवाई और समेकित कार्रवाई योजना जैसी रणनीतियां बनाई गईं। बाद में नक्सल विरोधी अभियान और नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए संचार माध्यमों को विकसित करने और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को भत्ते देने के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत यह भत्ता केंद्र सरकार राज्यों को देती है। इसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों और थानों के लिए भी धन का आवंटन किया जाता है। नक्सली हमलों की कड़ी चुनौती के बीच आठ मई 2017 को माओवादी हिंसा से प्रभावित दस राज्यों में एकीकृत कमान के गठन की पहल करते हुए सभी राज्यों की साझा रणनीति बना कर एक आठ सूत्रीय समाधान तैयार किया गया। इसके अंतर्गत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और वामपंथी उग्रवाद के वित्त पोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल करने की जरूरत बताई।

इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नक्सलवाद से निपटने की सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में गहरा फर्क देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुलिस की पुनर्वास नीति के अंतर्गत वादे तो बेहद लुभावने किए गए, जबकि नीतियों को लागू करने में नाकामी छिपी नहीं है।

■ डॉ. ब्रहमदीप अलूने
(वरिष्ठ पत्रकार)

राज-विचार

सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा

तेलंगाना में महिला डॉक्टर के साथ कुछ अपराधियों ने जिस तरह की दरिंदगी की, उससे पूरा देश सदमे में है और गुस्से से भरा है। एक बार फिर देश और समाज सड़क पर है। मगर सवाल यह है कि ऐसे ही समाज बार-बार सड़कों पर कब तक उतरता रहेगा।

तेलंगाना में एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ अपराधियों ने जिस तरह की दरिंदगी की, उससे पूरा देश सदमे में है और गुस्से से भरा है। जैसे-जैसे घटनाक्रम का क्रूर सच बाहर आ रहा है, समाज खुद पर शर्मसार हो रहा है। हाल के वर्षों में ऐसी असंख्य दर्दनाक खबरों के साथ जीने को हम अभिशप्त रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम यौन मनोरोगियों के देश में हैं जिसमें समूची स्त्री जाति के अस्तित्व और अस्मिता पर संकट उपस्थित है। दरअसल, आज यह सवाल हर किसी के मन में है कि इस वहशी समय में वे कैसे बचाएं अपनी बहनों-बेटियों को? उन्हें घर में बंद रखना समस्या का समाधान नहीं। अपनी जिंदगी जीने का उन्हें पूरा अधिकार है। वे सड़कों पर, बसों व ट्रेनों में निकलेंगी ही। हर सड़क पर, हर गली-मोहल्ले में, हर स्कूल-कालेज में पुलिस की तैनाती संभव नहीं है। आमतौर पर कानून और पुलिस का डर लोगों को अपराध करने से रोकता है। यह डर तो अब अब रहा नहीं। वैसे भी हमारे देश के कानून में जेल, बेल, रिश्वत और अपील का इतना लंबा खेल है कि न्याय के इंतजार में एक जीवन खप जाता है। दरिंदों के हाथों बलात्कार की असहनीय शारीरिक, मानसिक पीड़ा और फिर अमानवीय मौत झेलने वाली देश की हमारी बच्चियों और किशोरियों के लिए हमारे भीतर जितना भी दर्द हो, हमारी व्यवस्था के पास उस दर्द का क्या उपचार है? संवेदनहीन पुलिस, सियासी हस्तक्षेप, संचिकाओं में वर्षों तक धूल फांकता दर्द, भावनाशून्य न्यायालय, बेल का खेल और तारीख पर तारीख का अंतहीन सिलसिला। कुछ चर्चित मामलों को छोड़ दें तो सालों की मानसिक यातना के बाद निचले कोर्ट का कोई फैसला आया भी तो उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और दया याचिकाओं का लंबा तमाशा! स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। इन परिस्थितियों में इस बात की पूरी आशंका है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेकर सड़कों पर बलात्कारियों को सजा देने लगें।

महिलाओं के साथ यौन अपराध पहले भी होते रहे थे, लेकिन इन फिल्मों की सर्वसुलभता के बाद बलात्कार के आंकड़े आसमान छूने लगे हैं। इन फिल्मों का सेक्स सामान्य नहीं है। परिपक्व लोगों के लिए तो यह सब मनोरंजन और उत्तेजना के साधन हो सकते हैं, लेकिन अपरिपक्व और कच्चे दिमाग के बच्चों, किशोरों, अशिक्षित या फिर अल्पशिक्षित युवाओं पर इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है वह भयावह या तेलंगाना जैसी वारदातों के रूप में सामने आता है। जो भी हो अब एक बार फिर देश और समाज सड़क पर है। एक बेटी के लिए और उन तमाम बेटियों के लिए जो दरिंदगी का शिकार हो चुकीं। मगर सवाल यह भी है कि ऐसे ही समाज बार-बार सड़कों पर कब तक उतरेगा। ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही, जो देश और समाज में बलात्कार के खिलाफ एक सशक्त वार हो और दरिंदगी करने वालों के लिए कड़ा सबक।

जल की शुद्धता पर विचार जरूरी

अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि भारत के भूजल में हानिकारक यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानकों से कहीं अधिक है। दूषित भूजल से देश के कई हिस्सों में कैंसर तक के मामले सामने आए हैं। यह स्थिति हाथ से बाहर जाए, उससे पहले हालात सुधारने के उपाय शुरू कर देने होंगे।

अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि भारत के भूजल में हानिकारक यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानकों से कहीं अधिक है। यह स्थिति हमें चिंतित करने वाली इसलिए भी है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के लिए प्रति लीटर पेयजल में 30 माइक्रोग्राम यूरेनियम की मात्रा को सुरक्षित माना है। विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस की भी मानें तो सिंधु और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र का तकरीबन 60 फीसद भूजल दूषित हो चुका है। आंकड़ों में कहा गया है कि 200 मीटर की गहराई पर मौजूद भूजल का बड़ा हिस्सा दूषित हो चुका है वहीं 23 फीसद भूजल अत्यधिक खारा है। 37 फीसद भूजल में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। चूंकि, दूषित भूजल में खतरनाक रोग उत्पन्न करने वाले जीव पाए जाते हैं। लिहाजा यह स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

दूषित भूजल में पाए जाने वाले विषाणु पीलिया, पोलियो, गैस्ट्रो इंटराइटिस और चेचक जैसे रोगों को जन्म देते हैं, वहीं जीवाणुओं द्वारा अतिसार, पेचिस, मियादी बुखार, हैजा, सूजाक एवं क्षय रोग उत्पन होते हैं। आर्सेनिक के अलावा दूषित भूजल में कैडमियम, लेड, मरकरी, निकल तथा सिल्वर की मात्रा भी बढ़ जाती है जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। दूषित भूजल में लोहा, मैंगनीज, कैल्सीयम, बेरियम, बोरान एवं अन्य लवणों जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट और कार्बोनेट इत्यादि की अधिकता भी अब मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। आंकड़े के मुताबिक हर आठ सेकंड में एक बच्चा दूषित भूजल के सेवन से काल का ग्रास बन रहा है। हर साल पचास लाख से अधिक लोग दूषित भूजल के सेवन से मौत के मुंह में जा रहे हैं।

गौर करें तो यहां समस्या सिर्फ भूजल का दूषित भर होना नहीं है। विडंबना यह भी है कि भूजल स्तर में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसलिए कि भारत में भूजल का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में तो भूजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जबकि अन्य क्षेत्रों में इसकी कमी है। भूजल जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उचित उपयोग और संरक्षण होना चाहिए। इसलिए और भी कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूजल का व्यवहार अत्यधिक जटिल है। जीईसी 1997 के दिशा निर्देशों एवं संस्तुतियों के आधार पर देश में स्वच्छ जल के लिए भूजल संसाधनों का आकलन किया गया। देश में कुल वार्षिक पुनः पूरणयोग्य भूजल संसाधनों का मान 433 घन किमी है। प्राकृतिक निस्सरण के लिए 34 बीसीएम जल स्वीकार करते हुए नेट वार्षिक भूजल उपलब्धता का मान संपूर्ण देश के लिए 399 बीसीएम है। वार्षिक भूजल का मान 231 बीसीएम है जिसमें सिंचाई उपयोग के लिए 213 बीसीएम तथा घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल का मान 18 बीसीएम है।

भारत के जल संसाधन पर नजर दौडाएं तो भारत में विश्व के जल संसाधनों का 4 फीसद भाग पाया जाता है। इसका लगभग एक तिहाई भाग वाष्पीकृत हो जाता है तथा 45 फीसद भाग ढाल के अनुरूप बहकर तालाबों, झीलों और नदियों में चला जाता है। धरातलीय जल तथा पुनर्भरण योग्य भूमिगत जल से 1,869 घन किमी जल उपलब्ध है और इनमें से केवल 60 फीसद यानी 1,121 घन किमी जल का लाभदायक उपयोग किया जाता है। भूजल पीने के पानी के अलावा पृथ्वी में नमी बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है। जानना जरूरी है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सालाना मीठे व स्वच्छ पानी की खपत अधिक होती है। विश्व बैंक के विगत चार साल के आंकड़ों के अनुसार घरेलू, कृषि व औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिवर्ष 761 बिलियन घन मीटर जल का इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में पानी की कमी बढ़ गई है और उसका मूल कारण भूजल का दूषित होना ही है। भौगोलिक परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो भारत के पठारी भाग भूजल की उपलब्धता के मामले में कमजोर हैं। देखा जाए तो लगातार गिरता भूजल सिर्फ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड या बिहार के सीतामढ़ी तक ही सीमित नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल स्तर 70 फीसद तक नीचे पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान समय में भारत के 29 फीसद विकास खंड भूजल के दयनीय स्तर पर हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक लगभग 60 फीसद विकास खंड चिंतनीय स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि देश में जल संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि भूजल के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट प्रभावी कानूनी ढांचे का अभाव बना हुआ है। नतीजा भूजल न सिर्फ बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है बल्कि उसके स्तर में भी भारी गिरावट आ रही है। हैरान करने वाला तथ्य यह कि इस गहराते संकट का असर दिखने के बाद भी इसके बचाव के लिए लिए कोई कारगर उपाय नहीं हो रहा है। नतीज हर वर्ष अरबों घन मीटर भूजल दूषित हो रहा है। समझना होगा कि भारत सालाना जल की उपलब्धता के मामले में चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से बहुत पीछे है। ऐसे में अगर दूषित और गिरते भूजल को बचाने का समुचित उपाय नहीं किया गया तो हालात खतरनाक स्तर तक पहुंच सकते हैं।

उचित होगा कि सरकार दूषित और गिरते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपायों के साथ कुओं और तालाबों के संरक्षण, सिंचाई के स्रोतों के विकास और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में जल मित्रों के जरिए जनभागीदारी के साथ जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को गति दे। जलाशयों के जल का समय-समय पर परीक्षण करा नियमित सफाई सुनिश्चित करे। जनसाधारण में जल प्रदूषण के प्रति जागरुकता फैलाए। देश के तटवर्ती भागों में समुद्री जल का निर्लवणीकरण करके जल का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करे। देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के पांच गांवों में दूषित भूजल की वजह से कैंसर के मामले सामने आए हैं। दूषित भूजल से आंत के कैंसर, एक्जिमा, हेपेटाइटिस और लीवर संबंधी जानलेवा बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। गांव वालों का तो यह भी कहना है कि पिछले पांच साल के दौरान कई लोग इन बीमारियों की वजह से मारे जा चुके हैं।

भारत में तकरीबन 80 फीसदी ग्रामीण आबादी पीने के पानी के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भर है। इनमें उत्तर प्रदेश में ही स्थित गोरखपुर जैसे जिले भी शामिल हैं जहां संदूषित जल के कारण होने वाली महामारी हमेशा से चर्चा में रहती है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे तत्व हैं जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में इंसेफलाइटिस, पीलिया और टायफाइड जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। इन बीमारियों का शिकार ज्यादातर गरीब लोग हैं जो कि न्यूनतम स्वच्छता हालात में जिंदगी बिताते हैं। इस पर नियंत्रण की जरूरत है।

पानी की शुद्धता इसलिए भी चिंता का बड़ा कारण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जलस्तर की जो हालत होने वाली है, उसमें पीने जितना पानी मिल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर साफ और प्रदूषित पानी की बात ही बेमानी होगी। इसलिए स्वच्छ पानी के साथ जल की उपलब्धता पर भी बात करनी होगी।

■ रीता सिंह
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

एक समाज के तौर पर हम विफल हो चुके हैं। हमें सख्त से सख्त कानून की जरूरत है। ये सब जल्द खत्म होना चाहिए। सजा सख्त नहीं होगी, हम नहीं सुधरेंगे।

अक्षय कुमार, अभिनेता

क्या इन राक्षसों को सजा या फिर कानून का कोई डर नहीं है, हम एक व्यवस्था के रूप में और एक समाज के रूप में कहां गलत हो रहे हैं? इसका जवाब ढूंढना होगा।

यामी गौतम, अभिनेत्री

सत्यार्थ

कार्ल मार्क्स की समझदारी

एक युवक बहुत समझदार एवं नेक था। वह निर्धनों व शोषितों पर अत्याचार होते हुए देख नहीं सकता था। वह सदैव सोचता रहता था कि कैसे समाज से शोषक और शोषित वर्ग की खाई को पाटा जा सकता है। कैसे समानता आ सकती है एवं सबका जीवन अच्छा हो सकता है। यही सोचते हुए एक दिन वह कहीं जा रहा था कि उसकी नजर दीवार पर पुताई कर रहे एक श्रमिक पर पड़ी। उस युवक ने महसूस किया कि वह श्रमिक पुताई तो कर रहा था, पर इस ढंग से कि सामान व समय दोनों की बर्बादी हो रही थी। यह देख उससे रहा नहीं गया। वह उसके पास जाकर बोला-'मित्र! क्या तुम ऐसी विधि सीखना चाहोगे, जिसमें पुताई अच्छी तरह हो जाए और समय व सामान भी कम लगे।' श्रमिक उसे अचरज से देखने लगा। उसका मालिक भी वहीं पर खड़ा था। दोनों ने विचार करके कहा-'हां भाई! यदि तुम ऐसी कोई विधि जानते हो तो हमें अवश्य बताओ।' उस युवक ने कमीज की आस्तीन ऊंची चढ़ाई व पुताई का सामान लेकर ऊपर चढ़ गया। शाम होने से पहले ही उसने अपना पूरा काम खत्म कर दिया। जब युवक जाने लगा, तो मालिक ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे पारिश्रमिक देना चाहा। उसने यह कहते हुए पारिश्रमिक उसी मजदूर को दे दिया कि यह कार्य तो उसी का था, उसने तो बस, थोड़ी सी बुद्धि ही लगाई थी। वह युवक कोई और नहीं कार्ल मार्क्स था। मार्क्स ने ही साम्यवाद के रूप में पूरी दुनिया को एक ऐसी संकल्पना दी है, जिसमें इंसान का इंसान के हाथों शोषण संभव नहीं होता। इसकी व्यवहारिकता को लेकर भले ही बहस होती रहे, मगर इसमें दो राय नहीं कि मार्क्स के विचार शोषितों के हाथ मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण हथियार साबित हुए हैं।

■ राधा नावीज

इजराइल स्थित जिस कंपनी ने भारत समेत बीस देशों की नामी शख्सियतों के व्हाट्सएप में सेंध मारी है, उसने सबसे खतरनाक वायरस पेगासस का इस्तेमाल किया है। यह वायरस इतनी आधुनिक तकनीक वाला है कि जिस मोबाइल धारक की जासूसी करनी हो, उसके मोबाइल में यह लिंक के माध्यम से खुद इंस्टॉल हो जाता है। इस तरह साइबर हमलावर अथवा हमलावर समूह के पास मोबाइल का पूरा संचालन आ जाता है।

पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी और Pegasus सॉटवेयर को लेकर कई खबरें आई हैं। व्हाट्सएप का आरोप है कि पेगासस के जरिए व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी की जा रही थी। यह काफी गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर यूजर्स की प्रिवेसी का उल्लंघन किया जा रहा था। पेगासस को लेकर यूजर्स के मन में एक डर बना हुआ है।

पेगासस 2.0

सॉफ्टवेयर पेगासस के पहले वर्जन में हैकिंग के लिए वायरस को एक लिंक के तौर पर एसएमएस या व्हाट्सएप मेसेज के जरिए भेजा जाता था। इस लिंक पर क्लिक करते ही यूजर का डिवाइस हैक हो जाता था। पेगासस का लेटेस्ट वर्जन और भी खतरनाक है। यह अब केवल एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के यूजर के फोन में एंटर कर सकता है।

व्हाट्सएप में सेंधमारी

पेगासस के आने से व्हाट्सएप के एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के कारण व्हाट्सएप को काफी सेफ माना जाता था, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी एनकोडेड मैसेजेस को नहीं देख सकती थी। हालांकि, पेगासस ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। इसकी वजह यह है कि मैसेज के डीकोड होने और यूजर के फोन में आने के बाद अटैचमेंट सहित उसे पेगासस के जरिए उसे बहुत आसानी से मॉनिटरिंग सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है।

अब तक क्या हुआ

व्हाट्सएप ने कैलिफॉर्निया के फेडरल कोर्च में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। व्हाट्सएप ने एनएसओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने सर्विस टर्म्स ऐंड कंडिशन को न मानते हुए अपना सॉफ्टवेयर डिवेलप किया और व्हाट्सएप मैसेजेज को हैक किया। वहीं, दूसरी तरफ एनएसओ ने व्हाट्सएप द्वारा लगाए गए इन आरोपों का खंडन किया है।

आपको शक हो तो क्या करें ?

अगर आपको जरा भी शक है कि आपके फोन पर पेगासस अटैक कर चुका है तो तुरंत अपने सभी पासवर्ड्स को बदल दें। सॉफ्टवेयर से बचने के लिए केवल डिवाइस को ही बदलना ही काफी नहीं, क्योंकि यह लॉगइन आईडी और पासवर्ड सहित हर तरह के डीटेल्स दर्ज कर लेता है।

कब और किनकी हुई जासूसी ?

पेगासस के जरिए 20 देशों में 1400 लोगों की जासूसी की गई। इसमें 20 भारतीय भी शामिल थे। यह जासूसी इसी साल 20 अप्रैल से 10 मई के बीच की गई। इसमें सरकारों, सैन्य अधिकारियों, विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया।

जासूसी करने वाला सबसे खतरनाक

वायरस है पेगासस

व्हाट्सएप यूजर्स के लिए पेगासस बड़ा खतरा

पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी और Pegasus सॉफ्टवेयर को लेकर कई खबरें आई हैं। व्हाट्सएप का आरोप है कि पेगासस के जरिए व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी की जा रही थी। यह काफी गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर यूजर्स की प्रिवेसी का उल्लंघन किया जा रहा था। पेगासस को लेकर यूजर्स के मन में एक डर बना हुआ है। आज हम यहां आपको बताने वाले हैं कि कैसे पेगासस एक आम यूजर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही हम इससे बचने के तरीके भी जानेंगे।

भारत में क्या हुआ ?

भारत में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कथित तौर पर पत्रकारों और ऐक्टिविस्ट्स को टारगेट करने के लिए किया गया है। कई यूजर्स, जिनके वॉट्सऐप चैट हैक हुए हैं, उन्होंने यह शिकायत की है कि हैकिंग का ताल्लुक भीमा कोरेगांव मामले से है। इसकी बजाय की मेसेजिंग में दिग्गज व्हाट्सएप को कटघरे में किया जाए, देश की आईटी मिनिस्ट्री ने 4 नवंबर तक कंपनी ने डीटेल रिपोर्ट मांगी है।

हमले को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पहचान पाते

पेगासस मालवेयर की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके हमले का पता मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं लगा पाते हैं। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड और आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल में अगर साइबर हमला हुआ तो ये कंपनियां तुरंत इसकी पहचान नहीं कर पाएंगी।

2016 में आईफोन-6 पर हुआ था पहला हमला

पेगासस हमले का पहला मामला 2016 में आईफोन-6 पर हुआ, जबकि एप्पल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'आईओएस' को सबसे सुरक्षित माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मसूद ने शिकायत की कि उनके आईफोन-6 में एसएमएस पर लिंक भेजकर जासूसी करने की कोशिश की गई। तब एप्पल ने इस शिकायत को तकनीकी कमी बताकर मामला निपटा दिया था।

45 से ज्यादा देशों में नेटवर्क

पिछले साल सितंबर में टोरंटो विश्वविद्यालय से संबद्धित 'द सिटीजन लैब' ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पेगासस का नेटवर्क 45 देशों में है, जो अब और फैल चुका होगा। इस लैब ने दिखाया कि किस तरह पेगासस वायरस 'जीरो डे एक्सप्लॉइट्स' नाम की विशेष प्रक्रिया के जरिए साइबर हमला करता है। यह पूरी तरह से अनजान प्रक्रिया है, जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियां तक अनभिज्ञ हैं। इसी तरह मैसेंजर कंपनियां जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर आदि भी इसके हमले को नहीं पहचान पाती हैं। इसमें टारगेट यूजर के मोबाइल पर लिंक भेजा जाता है, जिसे यूजर क्लिक न भी करे, तब भी वायरस मोबाइल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा।

यूरोपीय मालिकाना हक वाली कंपनी है एनएसओ

जिस कंपनी पर व्हाट्सएप में जासूसी का आरोप है, वह इजराइल में स्थित है, लेकिन उसका मालिकाना हक है यूरोपीय कंपनी के पास है। फरवरी में यूरोप की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म नोवाल्पिना कैपिटल एलएलपी ने एनएसओ को सौ करोड़ डॉलर में खरीद लिया था। हैकिंग के आरोपों पर नोवाल्पिना कैपिटल एलएलपी ने कुछ महीने पहले यह ऐलान किया था कि कंपनी में काम करने के तौर-तरीकों के लिए नई रूपरेखा तैयार की जा रही है।

जमाल खागोशी हत्या के षडयंत्र में हुआ था इस्तेमाल

अमेरिकी पत्रकार जमाल खागोशी की हत्या में भी इस बेहद आधुनिक वायरस का इस्तेमाल हुआ। इस बात का खुलासा पिछले साल दिसंबर में हुआ, जब खागोशी के दोस्त उमर अब्दुल्लाजीज ने पेगासस हमले की शिकायत तेल अबीब में दर्ज कराई। यह शिकायत एनएसओ के खिलाफ दर्ज कराई गई कि उसने खाशोगी की हत्या का षडयंत्र रचने के लिए उन दोनों के बीच की बातों की जासूसी की। गौरतलब है कि उसी साल दो अक्टूबर को जमाल खाशोगी की इस्तांबुल में हत्या कर दी गई थी।

हर मैसेज में इंक्रिप्ट तकनीक सिर्फ व्हाट्सएप के पास

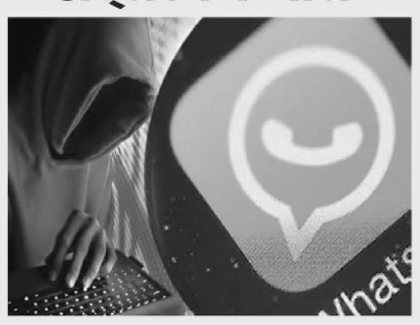

जहां हर दिन तकनीकी आधुनिक हो रही है, ऐसे में इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अभी तक हर मैसेज को इंक्रिप्ट करने की तकनीक सिर्फ व्हाट्सएप के पास है। व्हाट्सएप ने 2016 में इसे सबसे पहले शुरू किया। एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन तकनीक का मतलब है कि संदेभ भेजने के बाद एक कोड में बदल जाता है जिसे संदेश प्राप्त करता है डिस्क्रिप्ट करके पढ़ सकता है। कोई तीसरा व्हाट्सएप के संदेश नहीं पढ़ सकता। हालांकि हालिया जासूसी घटना के बाद व्हाट्सएप की यह तकनीक भी मात्र दावा ही रह गई है। पर कोई दूसरी मैसेंजर एप ऐसा दावा नहीं करती कि उसके सभी मैसेज इंक्रिप्टेड हैं। टेलिग्राम एप में सिर्फ 'सीक्रेट चैट' में किए गए संवाद को ही इंक्रिप्ट किया जाता है। लगभग इसी तरीके से फेसबुक मैंसेजर में भी मैसेज को इंक्रिप्ट कर सकते हैं पर यह वैकल्पिक है।

भीमा कोरेगांव मामले के वकीलों की जासूसी

एलिगार परिषद के आरोपी, भीमा कोरेगांव केस के वकील, दलित कार्यकर्ता, रक्षा और रणनीति बीट के एक पत्रकार और दिल्ली विश्वविद्यायल के एक प्रोफेसर समेत करीब दो दर्जन लोग व्हाट्सएप जासूसी के पीड़ित हैं। जेल में बंद सुधा भारद्वाज की वकील शालिनी गेरा ने कहा कि उन्हें लगातार स्वीडन के नंबर से वीडियो कॉल आ रही थीं। मामला खुलने के बाद वह समझ पाई हैं कि वह सब जासूसी के लिए किए गए वायरस हमले के तहत था। इसी मामले में बंद एक अन्य आरोपी सुरेंद्र के वकील निहाल सिंह राठौर के व्हाट्सएप की भी जासूसी हुई। तेलंगाना उच्च न्यायालय के वकील रविंद्रनाथ भल्ला ने बताया कि 7 अक्टूबर को उनके पास द सिटीजन लैब का मैसेज आया, जिसमें उन्हें उनके व्हाट्सएप की जासूसी के बारे में बताया गया था। फिर उन्हें व्हाट्सएप ने आधिकारिक मैसेज से यह जानकारी दी।

अनइंस्टॉल करने का फिलहाल कोई तरीका नहीं

पेगासस को अनइंस्टॉस करने का फिलहाल कोई तरीका पता नहीं चल पाया है। यह इतना खतरनाक है कि यह फोन के फैक्ट्री रीसेट होने के बाद भी उसमें मौजूद रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बचने का केवल एक ही तरीका है और वह है नया डिवाइस खरीदना। नए डिवाइस में पुराने सभी लॉगइन डीटेल्स को बदलना ही इससे बचने का अकेला तरीका है।

बड़ी कंपनियों के डिवाइस भी सुरक्षित नहीं

ओपन इंटरनेट ऐडवोकेसी ग्रुप Access Now के एशिया पॉलिसी डायरेक्टर और सीनियर इंटरनेशनल काउंसलर रमन जीत सिंह चीमा ने कहा कि सर्वेलन्स टेक फर्म जैसे एनएसओ और अन्य कंपनियां इन क्षमताओं की मार्केटिंग करती हैं, ताकि वे क्लाइंट्स को विक्टिम के स्मार्टफोन की हर ऐक्टिविटी पर नजर रखने की सहूलियत दे सकें। इसमें जीमेल, आईमेसेज, फेसबुक और वाइबर जैसी सर्विसेज भी शामिल हैं। सितंबर में गूगल की प्रॉजेक्ट जीरो टीम ने ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बड़े खतरे के बारे में बताया था जो डिवाइस को पूरा ऐक्सेस कर लेता है। गूगल के थ्रेट ऐनालिसिस ग्रुप ने भी इसके लिए एनएसओ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह शाओमी, सैमसंग, ओप्पो और गूगल के पिक्सल सीरीज डिवाइसेज को भी प्रभावित किया है।

एप्पमेकर की मदद से आप भी कर सकते है एप का निर्माण

एप्पमेकर एक एप निर्माण प्लेटफॉर्म है, जो हर किसी को आपकी अपनी आईफोन एप, एंड्राइड एप एवं एचटीएमएल5 मोबाइल फॉरमेट वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है- बिना किसी कोडिंग की आवश्यकता के।

एप्पमेकर का उपयोग कौन कर सकता है?

हम हर किसी के लिए एप की कल्पना करते हैं और हम इसे पूरा करना चाहते हैं। कोई भी अपनी सामग्री को शेयर करना चाहे तो आसान और प्रभावशाली तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए एप बना सकता है। चाहे वे ब्लॉगर, म्यूजिशियन, छोटे बिजनेस, पब्लिशर्स, गैर-लाभकारी, या कोई भी दूसरा हो। अगर आपके पास शेयर करने के लिए सामग्री है, तो इसके साथ बनाने के लिए एक एप उपलब्ध है।

मुझे एप्पमेकर क्यों उपयोग करना चाहिए? यह बहुत सरल है

पारंपरिक तौर पर, एक एप्प को मूल रूप से तैयार करने में बहुत अधिक समय और पैसे की आवश्यकता रहती है... और अक्सर एक इंजीनियरिंग डिग्री भी, लेकिन एप्पमेकर ने आपको अपना स्थानीय एप बनाते हुए इन उलझन भरे भागों का एक कोड-रहित समाधान देते समय खास ख्याल रखा है, वह भी कुछ ही मिनटों में।

यह सुविधाओं से पूरी तरह भरा-हुआ है

बिल्ट-इन अधिसूचना, एचटीएमएल5 फंक्शन, स्थानीय हाई-रेजोल्यूशन फोटो गैलरी, ब्रांडिंग और डिजाईन कस्टमाइजेशन, लाइव अपडेट के साथ और भी बहुत कुछ, आप अपनी सामग्री को दिखाने के लिए एक दमदार, उच्च गुणवता का मोबाइल एप बनाने में सक्षम होंगे।

यह सस्ती है

असंख्य अपडेट के साथ और बिना किसी कीमत के आप जितने बनाना चाहे उतने एप बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा सुविधाएं और अधिक कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय अपग्रेड कर सकते हैं एक हमारे सुलभ शुल्क युक्त संस्करणों में अपग्रेड कर सकते हैं, जो किसी iPhone डेवलपर द्वारा आपके लिए एक एप बनाने में खर्च हजारों डॉलर से बहुत कम है।

यह एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म है

पुराने समय में एंड्राइड एप और एक आईफोन एप बनाने का एकमात्र तरीका किसी मोबाइल डेवलपर की सेवाएं प्राप्त करना ही होता था। एप्पमेकर प्लेटफॉर्म आपको पूरी तरह से कस्टम की गई एंड्राइड एप तुरंत प्रकाशित करने देता है और इसके साथ ही स्थानीय एप्प संस्करण को आईट्यून्स एप्प स्टोर में दर्ज करता है - मात्र एक क्लिक से।

यह आपकी सामग्री को प्रदर्शित करने का बेहतरीन तरीका है

एक एप आपको उपयोगकर्ताओं के हाथों में नवीनतम सामग्री को तुरंत पहुंचाने की अनुमति देता है। एप्पमेकर प्लेटफॉर्म की सुविधाओं और फंक्शनों का लाभ लेते हुए, आप अपने दर्शकों को कभी भी, कहीं भी एक उत्तम मोबाइल अनुभव के साथ व्यस्त रख सकते हैं।

अपने डैशबोर्ड के जरिए एप नियंत्रण करें

अपने सभी एप (सिर्फ एक क्यों?) एक जगह पर ट्रैक करें और उनमें बदलाव एवं अपडेट करने के लिए आसानी से पहुंच प्राप्त करें। आप अपने उपयोगकर्ताओं को पुश नोटिफिकेशन भेज, अपने एप मैसेज देख और मात्र कुछ क्लिक से अपनी फीड को अपडेट भी कर सकते हैं।

अपने एप की बनावट और फंक्शन को कस्टमाइज करें

- कस्टम आइकॉन अपलोड करें, अपने मुख्य मेनू पेज के लिए स्क्रीन की तस्वीरें और बैकग्राउंड स्प्लैश करें। आपके मुख्य मेनू लेआउट को अपना एप थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए चुनें।
- आपका कोई ब्रांड या बिजनेस है, जिसके लिए एप बना रहे हैं? अपनी कलर स्कीम को मिलाएं और नियमित उपस्थिति के लिए एप के हरेक पेज पर अपने लोगों के साथ एक चयनित बैकग्राउंड को रखें।
- यहां, आप चुन सकते हैं किस प्रकार की नेविगेशन, शेयरिंग और उन्नत सुविधाएं आपके एप में मौजूद हैं। जैसे आप चाहें इसे दमदार या सरल बनाएं और कमेंट और शेयरिंग प्रणाली का लाभ लें, जो प्रेरित हैं सामाजिक बनें, एप समुदाय में प्रोत्साहन के लिए।

टैब्स के साथ अपनी एप्प में सामग्री जोड़ें

- ब्लॉग, नवीनतम समाचार तथा लेख, फोटो गैलरी और वीडियो जैसी समृद्ध सुविधाओं के साथ अपने एप्प को सुसज्जित करें। मैसेज बोर्ड, लाइव चैट रूम्स, और वर्गीकृत विज्ञापन जैसे सम्वादात्मक विकल्प वहां उपलब्ध हैं। संपूर्ण एमकॉमर्स सूची कार्य, बुकशेल्फ एवं संगीत पुस्तकालय, सभी आपको अपने एप से कमाई अर्जित करने में मदद करते हैं। यहां तक कि एक पूरी तरह से अनुकूलन योग्य एचटीएमएल 5 टैब भी है, जिसे हम एक खाली स्लेट कहना पसंद करते हैं - इसकी कार्यक्षमता पूरी तरह से आपके उपर निर्भर करती है।
- आपके एप का लेआउट पूरी तरह से आपके उपर है और आप जितनी मर्जी चाहें उतने टैब्स जोड़ सकते हैं। आपकी सामग्री को दर्शाने के लिए असंख्य तरीके हैं।

अपनी एप का रियल टाइम में पूर्वावलोकन करें

हमारे लाइव प्रीव्यू फंक्शन के साथ अपने मोबाइल डिवाइस पर अपने एप से खेलें और प्रयोग करें। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि विभिन्न डिवाइसों पर आपका एप कैसा दिख सकता है, या आधे मन से किसी एमुलेटर पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइव लिंक किसी भी स्मार्टफोन पर एसएमएस, ईमेल या एक क्यूआर कोड शूटिंग द्वारा भेज सकते हैं, जो आपके एप को आपके फोन पर खोल देगा, ताकि आप एप के हरेक फंक्शन को बनाते समय जांच कर सकें।

अपनी एप को प्रकाशित करें और आनंद लें

- अब आप सबसे बेहतर भाग में आ चुके हैं। अपने एप को मार्केट में प्रकाशित करना। जैसा कि आप अपने एप को एप्पमेकर प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं, आप सभी फंक्शनों का कार्यरत लाइव प्रीव्यू प्राप्त कर सकेंगे। अपने एप से प्यार में पड़ने के बाद, आप मात्र एक क्लिक से मार्केट में अपने एप प्रकाशित कर सकते हैं।
- सभी एप तुरंत हमारी स्थानीय एंड्राइड मार्केट और एचटीएमएल5 मोबाइल वेबसाइट के तौर पर में लाइव हो जाती हैं- बिल्कुल सही, तुरंत। आपके ग्राहक और प्रशंसक आपके एप्प का उसी दिन से उपयोग शुरू कर सकते हैं। अगर आपने हमारे किसी एक वितरण प्लान को चुना है, तो इसके साथ ही आपके एप गूगल प्ले मार्केट, एप्पल के आईट्यून्स एप स्टोर एवं आपकी पसंद के विश्व भर से हमारे दूसरे प्रीमियम एप वितरण भागीदारों को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अगर आप चाहें, आपके द्वारा एप्पमेकर में बनाई गई एप को आपके अपने डेवलपर खाते और आपके अपने ब्रांड नाम के तहत प्रकाशित किया जा सकता है। अब आपको केवल इतना करना है कि एक एप डेवलपर अपने रिज्यूमे में जोड़ना है और आप पूरी तरह तैयार हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

लारवा विरोधी सेल की तरफ से डेंगू लारवा के 6 मामलों की पहचान

■ जालंधर/नीरज

पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के लारवा विरोधी सेल की तरफ से शहर की अलग-अलग स्थानों पर 6 डेंगू लारवा मामलों की पहचान की गई।

लारवा विरोधी सेल की अलग -अलग टीम में अमनप्रीत, विनोद कुमार, हरप्रीत पाल, पवन कुमार, शेरसिंघ, राज कुमार, गुरविन्दर सिंह, राजविन्दर सिंह, सरबजीत, कमलदीप और अन्य शामिल थे की तरफ से एकता नगर फेस -2, न्यू गोपाल नगर, रत्न नगर, कोट बाबा दीप सिंह, नगर, लकशमीपुरा और बूटा मंडी और दूसरे क्षेत्रों की जांच की गई। इस अवसर पर टीम सदस्यों की तरफ से 393 घरों का दौरा करके 1659 लोगों को कवर करते 53 कूलरें और 395 अन्य वस्तुओं की जांच की गई। इस अवसर पर टीम सदस्यों की तरफ से लोगों को बताया गया कि मच्छरों की तरफ से डेंगू का लारवा ज्यादातर कूलरों में पैदा किया जाता है जिस से डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। उन्होंने बताया कि इस जांच मुहिम का मुख्य उद्देश्य मच्छरों की तरफ से डेंगू लारवा पैदा किये जाने वाले स्थानों की पहचान करना है।

कांग्रेस और JMM से रहें सावधान, वो झूठ और भ्रम फैला रहे हैं: मोदी

■ खूंटी/न्यूज नेटवर्क

खूंटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को यहां कहा कि भाजपा आदिवासी हितों की रक्षा करने और आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने खूंटी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल,जंगल और जमीन के अधिकार पर कोई आंच नही है और न आने दी जाएगी। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नजर केवल यहां के प्राकृतिक संसाधनों के लूट पर है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी झूठ और भ्रम फैला रहें हैं जिससे सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड के 19 साल होने पर उन्होंने कहा कि अब अगला पांच साल राज्य के लिए बेहद अहम है और इसमें राज्य को इतना ताकतवर,समृद्ध होना है ताकि वह फिर कभी पीछे मुड़कर नही देखे। झारखंड गठन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए ही वर्ष 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया गया और पहली बार अलग केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय बनाया गया जिसके मंत्री वर्तमान में खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा है। मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'जिला मिनरल फंड' की व्यवस्था की गई और इसके तहत झारखंड को पांच हजार करोड़ की राशि दी गई है जिससे आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए स्कूल-कॉलेज समेत अस्पताल एवं रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड को विकसित करने की जितनी जिम्मेदारी राज्य के लोगों को है उतनी ही केन्द्र सरकार के रूप में हमारी है और वह इसके लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होने खूंटी में 3000 सखी मंडलों की चर्चा करते हुए कहा कि घर-घर महिलाओं को सशक्त करने और आर्थिक तौर पर समृद्ध करने में सखी मंडलों का योगदान अभूतपूर्व है और इसमें मुद्रा योजना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में गरीबों के कल्याण की योजनाओं को झारखंड के सभी घरों में पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने की लोगों से अपील की।

लोकसभा में उठी PUBG पर रोक लगाने की मांग, स्पीकर ने कांग्रेस सांसद को दी हिदायत

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन लोकसभा में ऑनलाइन गेम पबजी (PUBG) पर रोक लगाने की मांग की गई। कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच. वसंत कुमार ने सरकार से मांग की कि वह ब्लू व्हेल, पबजी जैसे इत्यादि ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगा दें।

आपको बता दें कि पबजी जैसे ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध की मांग इसलिए उठ रही है ताकि लोग सुरक्षित रहे। क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें यह दावा किया गया कि पबजी खेलने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। या फिर मानसिक तौर पर वह परेशानियों का सामना कर रहा है।

क्या है PUBG ?

पबजी एक तरफ का ऑनलाइन गेम है। जो बिल्कुल युद्ध की तरह है। जहां पर 100 लोग या फिर 100 टीमें एक रणक्षेत्र में जीतने के लिए उतरती हैं। इस गेम में अब्बल आने पर चिकन डिनर होता है। यह कोई असल चिकन डिनर नहीं है यह एक तरह का सिब्बल है कि आपने इस मुकाबले को जीत लिया है।

सदन में कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस तरह के ऑनलाइन गेम पर बहुत से देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस तरह के ऑनलाइन गेम से बच्चों की मानसिक परिस्थितियों पर बुरा असर पड़ रहा है। जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो रही है। हालांकि लोकसभा में जब कांग्रेस सांसद बोल रहे थे उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका। दरअसल, सांसद महोदय बार-बार कागज देखकर पढ़ रहे थे।

इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि सांसद अपने-अपने घरों में प्रैक्टिस किया करें और एक-दो मिनट में अपनी बात सदन में रखा करें।

भारतीय सिख महिला ने करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से फैसलाबाद जाने का प्रयास किया

■ लाहौर/ब्यूरो

भारत की एक सिख महिला पाकिस्तान के करतारपुर दौरे के समय बिना वीजा के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से मिलने फैसलाबाद पहुंच गई, जिससे उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि करीब 20 वर्ष की मंजीत कौर नवम्बर के अंतिम हफ्ते में करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंची थी। कौर फेसबुक के माध्यम से उस व्यक्ति के संपर्क में थी और गुरुद्वारा में उसने उससे मुलाकात की और एक पाकिस्तानी महिला का परमिट दिखाकर उस व्यक्ति के साथ फैसलाबाद जाने का प्रयास किया। भारतीय श्रद्धालु हाल में खुले करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहिब जा सकते हैं लेकिन वे पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में नहीं जा सकते हैं। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (विस्थापित न्यास संपत्ति बोर्ड) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''यह पहली घटना है जिसमें किसी भारतीय सिख महिला ने नौ नवम्बर को करतारपुर कॉडोर खुलने के बाद से इस सीमित क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास किया है।'' उन्होंने कहा कि महिला पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ जाना चाहती थी लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उसे सीमित क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि महिला अमृतसर की है वहीं भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वह हरियाणा के रोहतक की है। ''सुरक्षा अधिकारियों ने भारतीय महिला को वापस भेज दिया और इस बारे में अपने समकक्ष को सूचित भी किया।''

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा रात के समय महिलाओं को सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए मुफ्त पुलिस सहायता का ऐलान

■ चंडीगढ़/न्यूज नेटवर्क

महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बढ़ रही चिंता के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रात 9 बजे से प्रात:काल 6 बजे के दरमियान महिलाओं को घर जाने के लिए उपयुक्त साधन न मिलने की सूरत में उनको सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए मुफ्त पुलिस सहायता मुहैया करवाने का ऐलान किया है। राज्य भर में यह सुविधा 100, 112 और 181 नंबर पर मौजूद होगी जिनके द्वारा संपर्क करने वाली महिला तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (पी.सी.आर.) के साथ जुड़ जायेगी। मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को यह सुविधा राज्य भर में लागू करने को यकीनी बनाने के आदेश दिए। घर से ले जाने और छोड़ने की सुविधा उन महिलाओं को हासिल होगी, जिनकी टैक्सी या थ्री -वीलर जैसे सुरक्षित वाहन तक पहुँच न हो। महिलाओं में सुरक्षा की भावना के तौर पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि यातायात के दौरान सम्बन्धित महिला के साथ कम- से -कम एक महिला पुलिस अधिकारी जरूर होनी चाहिए। डी.जी.पी. ने वृद्धि में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मोहाली, पटियाला और बठिंडा समेत अन्य बड़े शहरों में पुलिस हैड्क्वाटरों पर अलग से पी.सी.आर. वाहन मौजूद होंगे। हरेक जिले में इस स्कीम को अमल में लाने के लिए डी.एस.पी. / ए.सी.पी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध विंग) नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात होगी। इन महिला पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे।

खेत से प्याज उखाड़ ले गए चोर

■ मंदसौर/न्यूज नेटवर्क

बाजार में प्याज के आसमान छूते भावों के चलते अब प्याज की फसल किसान के खेत में भी सुरक्षित नहीं है। अपने किस्म के एक अनोखे मामले में जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर एक गांव में अज्ञात चोर एक किसान के खेत से 30,000रुपये कीमत की प्याज की फसल ही उखाड़ कर चुरा ले गये। नारायणगढ़ पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक आर एस बिलवाल ने बताया कि जिले के रिछा बच्चा गांव के किसान जितेन्द्र कुमार ने मंगलवार को आवेदन देकर शिकायत की है कि सोमवार रात को अज्ञात बदमाश उसके खेत से चार बीघा रकबे में बोई गई प्याज की लगभग सात क्विंटल फसल उखाड़ कर ले गये। इससे उसे लगभग 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने बताया कि किसान ने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि बदमाश खेत से कच्ची प्याज उखाड़ ले गये जबकि उसके हरे पत्ते खेत में ही पटक गये। पिछले कई माह से बाजार में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और सामान्यत: 15-20 रुपये प्रति किलो के भाव से मिलने वाला प्याज 80 -100 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है।बिलवाल ने बताया कि वह किसान के खेत पर जाकर मौके का मुआयना करने के बाद मामले में आगे जांच करेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह एक व्यापारी ने नासिक से गोरखपुर के लिये जाने वाले ट्रक में लदी 20-22 लाख रुपये कीमत की प्याज की चोरी की शिकायत पुलिस को की थी। यह ट्रक खाली हालत में शिवपुरी में मिला था जबकि उसमें लदा 40 टन प्याज ट्रक में नहीं था।

यह अमेरिका पर निर्भर है कि वह हमसे 'क्रिसमस पर क्या उपहार' चाहता है: उत्तर कोरिया

■ सियोल/न्यूज नेटवर्क

उत्तर कोरिया ने मंगलवार को फिर एक बार ट्रंप प्रशासन से कहा कि उनके पास परमाणु वार्ता को बचाने का बेहद कम समय बचा है और यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि उसे क्रिसमस पर उत्तर कोरिया से कौन सा उपहार चाहिए। उत्तर कोरिया के वरिष्ठ राजनयिक के हवाले से यह बयान वाशिंगटन और सियोल पर दबाव बनाने के लक्ष्य से दिया गया है। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने समझौते में एक-दूसरे को स्वीकार्य शर्तों के लिए अमेरिका को एक साल का समय दिया था, जो अब समाप्त हो रहा है। फरवरी में किम और ट्रंप के बीच वार्ता असफल रही थी क्योंकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया को आंशिक रूप से परमाणु कार्यक्रम बंद करने के बदले प्रतिबंध से बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर में स्वीडन में वार्ता भी असफल रही थी, जिसे उत्तर कोरिया ने अमेरिकियों का 'पुराना रुख और रवैया' बताया था।अमेरिकी मामलों को देख रहे उप विदेश मंत्री री थे सॉन्ग ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि अमेरिका बिना किसी वास्तविक हल के वार्ता की बार-बार पेशकश करके बस समय लेना चाहता है। सॉन्ग ने, ''अमेरिका द्वारा वार्ता की पेशकश डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) को बातचीत के लिए बाध्य करने और उसका इस्तेमाल अमेरिका में राजनीतिक स्थिति और चुनाव में करने की एक मूर्खतापूर्ण चाल के अलावा कुछ भी नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''अब जो किया जाना बाकी है, उसका विकल्प अमेरिका के पास है और यह पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि उसे क्रिसमस का क्या उपहार मिलेगा?''

रेप की घटनाओं के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहीं स्वाति मालीवाल को पुलिस ने जंतर-मंतर से हटने के लिए कहा

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से जंतर मंतर परिसर खाली करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने एक स्थायी आदेश का हवाला दिया है जिसके अनुसार स्थल पर शाम पांच बजे के बाद विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी है. हाल में हुई बलात्कार की घटनाओं के विरोध में मालीवाल आज जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गईं. उन्होंने पुलिस के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

स्वाति मालीवाल की क्या है मांग ?

1. निर्भया के बलात्कारियों को फांसी दो
2. पुलिस के संसाधन बढ़ाओ. 66,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में बढ़े
3. देश भर में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, दिल्ली में 45 बनें
4. पुलिस की जवाबदेही एवं आधुनिकरण
6. पूरे निर्भया फंड का इस्तेमाल हो

स्वाति मालीवाल का कहना है कि केन्द्र इन मांगों को माने उसके बाद ही अनशन तोड़ेंगी. बता दें कि हैदराबाद गैंगरेप और हत्या की वारदात सामने आने के बाद से ही देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. लोग आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं।

हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में सहायक पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) के तौर पर काम करने वाली युवती का जला हुआ शव 28 नवंबर की सुबह शादनगर में एक पुलिया के नीचे से बरामद किया गया था। घटना से एक दिन पहले ही वह लापता हुई थी. इस संबंध में चार आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार ने इस मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए मोबाईल वैन रवाना

■ जालंधर/नीरज

उप मंडल मैजिस्ट्रेट जालंधर -2 राहुल सिंधु और सिविल सर्जन जालंधर डा.गुरिन्दर कौर चावला की तरफ से तंदुरुस्त पंजाब मिशन के अंतर्गत जिले में खाध पदार्थों में मिलावट की जांच फूड सेफ्टी आन वील मोबाईल वैन को रवाना किया गया।

उप मंडल मैजिस्ट्रेट जालंधर -2 और डा.गुरिन्दर कौर चावला ने बताया कि इस मोबाईल वैन के साथ तैनात भोजन सुरक्षा विंग की तरफ से 31 दिसंबर तक जिले के हर कोने-कोने में जा कर खाध पदार्थों की गुणवत्ता को चैक करके मौके पर रिपोर्ट दी जायेगी। उनहोने बताया कि खाध पदार्थों की जांच के लिए यह मोबाईल वैन चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए मिलावट रहित भोजन को यकीनी बनाना है। उनहोने बताया कि यह अति आधुनिक मोबाईल वैन मौके पर ही मिलावटी खाना पदार्थों की जांच करन के समर्थ हैं जिस से लोगों की ओर से प्रयोग की जाने वाले भोजन पदार्थों की गुणवत्ता जांच में सहायता मिलेगी।

उनहोने कहा कि खाना पदार्थों की जांच वाली मोबाईल वैन की तरफ से 3 दिसंबर को फिलौर, 4 दिसंबर को गुराया, 5 दिसंबर को नूरमहल, 6 दिसंबर नकोदर, 9 से 11 दिसंबर शाहकोट और मलशियां, 12 दिसंबर

करतारपुर, 13 दिसंबर आदमपुर और भोगपुर, 16 दिसंबर मकसूदां क्षेत्र, 17 दिसंबर रामा मंडी, 18 दिसंबर माडल टाऊन, 19 दिसंबर को छोटी बारांदरी, 20 दिसंबर माडल हाऊस और बाकी रहते क्षेत्रों में 23 से 31 दिसंबर तक की ओर से प्रयोग की जाने वाले भोजन पदार्थों की जांच की जायेगी।

बैंकों के विलय से कोई नौकरी नहीं जाएगी, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी : सरकार

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न बैंकों के विलय से नौकरियां जाने की आशंका को खारिज करते हुए सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि इससे किसी की नौकरी नहीं जाएगी बल्कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी तथा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि विभिन्न बैंकों के विलय से वे मजबूत और प्रतिस्पर्धी होंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं खत्म हो।उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय से कर्मचारियों को अधिकतम लाभ होगा और विलय में उनके हितों को ध्यान में रखा रहा है। ठाकुर ने कहा कि विलय प्रक्रिया के दौरान हमने पर्याप्त सावधानी बरती है।उन्होंने कहा कि 1998 में नरसिम्हन समिति और बाद में लीलाधर समिति आदि ने बैंकों के विलय की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों (पीएसबी) का विलय कर उन्हें चार पीएसबी में बदलने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य सुदृढ़ बैंक तैयार करना है जो अधिक सामर्थ्यवान और लाभकारी होंगे। इस कवायद के तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा जबकि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय होगा। उन्होंने कहा कि यूबीआई का कुल कारोबार 2,08,000 करोड़ रुपये का है, जबकि पीएनबी का 11,82,224 करोड़ रुपये है। विलय के साथ, कुल कारोबार आकार 17,94,526 करोड़ रुपये होगा और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।